

Representation for extending date of Production of Permission of Textile Commissioner in case of Powerlooms

2922. SHRI G. M. BANATWALLA: Will the Minister of COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION be pleased to state:

(a) whether representations have been made to Government to extend the date by which the powerlooms were to produce to the Central Excise authorities the written permission of the Textile Commissioner for working powerlooms in order that licences may be retained for the manufacture of unprocessed cotton fabrics; and

(b) if so, what decision has been taken thereon?

THE MINISTER OF COMMERCE AND CIVIL SUPPLIES AND CO-OPERATION (SHRI MOHAN DHARIA): (a) Yes, Sir.

(b) As per the budget proposals of 1977-78 introduced in Parliament, compounded duty on powerlooms has been completely abolished and henceforth no excise licence will be required by the powerlooms. Other aspects are under consideration.

कृषि परियोजनाओं के लिए अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से सहायता

2923. श्री उपसेन :

श्री कल्याण जैन :

श्री जी० वाई० कृष्णन :

क्या वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने भारत में कृषि परियोजनाओं के लिए 20 करोड़ डालर का ऋण देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो यह ऋण किस परियोजनाओं पर खर्च होगा और उन राज्यों के नाम क्या हैं जहाँ ये परियोजनाएँ स्थित हैं; और

(ग) इसके फलस्वरूप कितने किसानों को लाभ पहुंचेगा ?

वित्त तथा राजस्व और बैंकिंग मंत्री (श्री एच० एम० पटेल) : (क) शायद माननीय सदस्य का अभिप्राय 20 करोड़ डालर के उस कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम—दूसरा ऋण परियोजना करार से है, जो भारत सरकार ने पहली जून, 1977 को अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ किया है जो आसान शर्तों पर ऋण देने वाली विश्व बैंक की एक संस्था है ।

(ख) इस राशि का उपयोग कृषि पुनर्वित्त और विकास बैंक द्वारा इस योजना में भाग लेने वाले भूमि विकास बैंकों और वाणिज्य बैंकों द्वारा देश भर में मुख्य रूप से लघु सिंचाई और फार्म पर विकास के लिए दिये जाने वाले ऋणों के सम्बन्ध में पुनर्वित्त की व्यवस्था करने के लिए किया जायेगा ।

(ग) इस योजना से लगभग दस लाख किसानों को लाभ पहुंचेगा और इस ऋण का कम से कम 50 प्रतिशत हिस्सा छोटे किसानों को दिया जाएगा ।

Exports from Calcutta Port

2924. SHRI K. A. RAJAN: Will the Minister of FINANCE AND REVENUE AND BANKING be pleased to state:

(a) whether crores of rupees in foreign exchange have been lost as a result of continued under-invoicing of exports from Calcutta Port during the last five years;